

न्यायालय अति० संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर०ए०एस० अति० संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या: 55/2017/अपील/एल.आर.एक्ट/कोटा

दायरा दिनांक: 10.5.2017

अन्तर्गत धारा: 75 राज० भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. राजेन्द्र आत्मज मथुरालाल जाति लश्करी निवासी ग्राम भीमपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

...अपीलाट

बनाम

- 1 रामनारायण
- 2 मथुरालाल
- 3 बाबूलाल पिसरान बिरधा जाति लश्करी निवासी ग्राम भीमपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
- 4 रामकन्या पुत्री बिरधा
- 5 प्रेमबाई पुत्री बिरधा
- 6 सुरेन्द्र पुत्र किशोर जाति लश्करी निवासीग्राम भीमपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
- 7 वीरू आत्मज किशोर
- 8 चुन्नु पुत्र किशोर जाति लश्करी निवासी ग्राम भीमपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
- 9 ग्राम पंचायत भीमपुरा जरिये सरपंच ग्राम भीमपुरा।

... रेस्पोजेन्ट



उपस्थित : श्री घनश्याम नागर अभिभाषक अपीलाट

श्री अतुल वशिष्ठ अभिभाषक रेस्पोजेन्ट्स 1 व 3 लगायत 6

निर्णय

दिनांक 8.02.2018

अपीलार्थी ने न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्र० सं० 8, 9/2015 बउनवान राजेन्द्र कुमार बनाम रामनारायण वगेरा (रिमांड प्रकरण-द्वारा न्याया० उपखण्ड अधिकारी कोटा) मे पारित निर्णय दिनांक 1.5.2017 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज० भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

- 1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि स्व० बिरधा पुत्र हरलाल के नाम ग्राम भीमपुरा मे दर्ज आराजी ख० नं० 232, 307, 307/1001, 680, 813, 867 कुल किता 6 रकबा 3.93 है० के संदर्भ मे पूर्व स्वीकृत नामान्तरकरण सं० 696 बहाल करने, बहाली का नोट अंकित कर राजस्व रिकार्ड मे मृतक खातेदार बिरधा के स्थान पर समस्त सुलभी वारिसों का नाम नामान्तरकरण सं० 696 अनुसार दर्ज किये जाने का तहसीलदार लाडपुरा द्वारा दिनांक 1.5.2017 को पारित निर्णय से व्यथित होकर अपीलाट द्वारा अपील इस आशय के साथ पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज कर रेस्पोजेन्ट के पक्ष मे इन्तकाल तस्दीक

10.02.2018

करने का आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि उक्त आराजी किता 6 रकबा 3.93 है0 अपीलांट के दादा बिरधा की स्वअर्जित कब्जे एवं खातेदारी की भूमि है जिस पर वह जीवन पर्यन्त काबिज रहे और उनके स्वर्गवास के बाद उनके द्वारा आलेखित कुल 5 किता रकबा 2.38 है0 आराजी पर वसीयत दिनांक 24.4.10 से बिरधा जी मृत्यु दिनांक 23.5.11 से अपीलांट बहैसियत मालिकाना काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त तथ्य अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यो साबित कर देने के बाद भी अपीलांट के पक्ष में इंतकाल तस्दीक नहीं कर इंतकाल सं0 696 को बहाल किये जाने का आदेश प्रदान कर त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया कि रेस्पो0 क्रम 1 व 2 ने अपीलांट के दादा व पिता के विरुद्ध दिनांक 5.11.2001 को न्यायालय में एक वाद प्रस्तुत किया था जिसके जवाब में स्वयं बिरधा द्वारा उक्त आराजी स्वअर्जित होना व रेस्पो0 क्रम-1 व 2 का उनके जीवनकाल में कोई हक व अधिकार उत्पन्न नहीं होना वर्णित किया था। उक्त तथ्यो का रेस्पो0 द्वारा खण्डन नहीं किया गया। रिकार्डेड खातेदार को राज0 काश्तकारी अधि0 के अन्तर्गत वसीयत करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत की प्रमाणिकता को स्वीकार किया है किन्तु रेस्पो0 को लाभ पहुंचाने के ध्येय से बिना किसी आधार व उज्र के उक्त आराजी को पैतृक होना मानकर निर्णय पारित करने में तहसीलदार लाडपुरा द्वारा त्रुटि की है। उक्त वाद को उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा दिनांक 9.12.2010 को खारिज किया गया जिसकी अप्रसन्नता से रेस्पो0 द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय को आराजी पेत्रिक है या स्वअर्जित है इसका श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है उक्त तथ्य बावत सक्षम न्यायालय में अपील जेरकार है जहां से निर्णय होना बाकी है। राज0 टीनेन्सी एक्ट की धारा 39 व 40 का गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही निर्णय दिनांक 25.1.2017 में निकाले गये निष्कर्ष के विपरीत रेस्पोडेन्ट के पक्ष में त्रुटिपूर्ण आदेश पारित कर दिया। अपीलांट द्वारा न्याया0 एसडीओ कोटा में प्रस्तुत अपील को दिनांक 26.3.2015 को सभी पक्षो को सुनकर निर्णय पारित करने हेतु रिमांड किया गया था जिसकी अपील रेस्पो0 1 व 2 द्वारा न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा में की गई उक्त अपील का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन कर दिनांक 25.1.2017 को खारिज किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने एसडीओ कोटा के रिमांड आदेश की पालना किये बिना जेरअपील आदेश पारित कर त्रुटि की है। इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि अपीलांट के पक्ष में आलेखित वसीयत पंजीकृत वसीयत है जो किसी भी प्रकार से संन्देहास्पद नहीं है। और न ही इस संबध में स्वयं रेस्पो0 द्वारा आपत्ति दर्ज करवाई गई है तथा नहीं रेस्पो0 द्वारा वसीयत के गवाहो से इस संबध में जिरह ही की गई है इस प्रकार आलेखित वसीयत का रेस्पो0 द्वारा किसी भी प्रकार से खण्डन नहीं करने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने भू राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) के विपरीत जाकर आदेश प्रदान कर त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर अपीलांट के पक्ष में इंतकाल तस्दीक करने का आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की गई।

- 2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण में बहस अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।
- 3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये जाहिर किया कि विवादित आराजी अपीलांट के दादा बिरधा की स्वअर्जित है। विवादित आराजी कुल 5 किता रकबा 2.38 है0 की बिरधा द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त वर्णित आराजी की वसीयत दिनांक 24.4.10 को अपीलांट के पक्ष में निष्पादित की है जो रजिस्टर्ड वसीयत है। उक्त आराजी पर बिरधा जी मृत्यु दिनांक 23.5.11 से अपीलांट बहैसियत मालिकाना काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा विवादित आराजी के विधिविरुद्ध तस्दीक नामा0 सं0 696 की अपील अपीलांट द्वारा न्यायालय एसडीओ कोटा में की गई जिसे स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार को रिमांड किया गया। एसडीओ के उक्त आदेश की अपील रेस्पो0 ने माननीय न्यायालय एडीसी में पेश की जिसे दिनांक 25.2.17 को खारिज कर दिया। इस प्रकार एसडीओ0 का आदेश बहाल रहा तहसीलदार ने दोनों पक्षो को सुना व वसीयत को सही माना किन्तु भूमि पैतृक होने

सं. 10/2017

से वसीयत का अधिकार नहीं होना माना, जबकि राज० काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत खातेदार आसामी को वसीयत करने का अधिकार प्रदत्त है। भूमि पैतृक होने का पत्रावली में कोई दस्तावेज नहीं है। रामनारायण व बाबूलाल ने एसीएम कोटा में बिरधा के खिलाफ भूमि पैतृक मानते हुये दावा किया जिसे खारिज कर दिया जिसकी अपील आरएए में जेरकार है। सक्षम कोर्ट को विवाद्यक तय करना है जिसे तहसीलदार ने कर दिया जिसका तहसीलदार को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। जो वाद आरएए में पेन्डिंग था उसे खारिज करवा लिया। दो अपील पेश की थी महेन्द्र के संबंध में कुछ नहीं लिखा फिर भी नामा० खारिज किया। आदेश दिनांक 1.5.2017 की दि० 9.5.2017 को अपील पेश की, दि० 4 व 5/5/17 को इंतकाल खोल दिया। न्यायालय अति० संभागीय आयुक्त कोटा से दिनांक 12.5.17 को स्थगन था दिनांक 9.5.2017 को रजिस्ट्री करवा दी। सरपंच इसी दिन नामान्तरकरण खोल दिया। बहस में आगे बताया कि सेक्शन 52 अपील के समय तक लागू होगी। अन्त में वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक करने का आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया।

- 4 रेस्पो० क्रम-2 दिनांक 5.7.2017 को स्वयं उपस्थित होकर प्रकरण में लिखित बहस प्रस्तुत कर वर्णित किया कि विवादित आराजी बिरधा का स्वअर्जित है पैतृक नहीं है। वसीयत के आधार पर अपीलांत विवादित आराजी पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। वसीयत के संबंध में रेस्पो० द्वारा की गई फौजदारी कार्यवाही में अनुसंधान अधिकार द्वारा वसीयत सत्य होना मानकर एफआर प्रस्तुत की गई जिससे वसीयत सही एवं सत्य होना प्रमाणित होता है। स्वयं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी वसीयत को प्रमाणित होना स्वीकार किया है। सेटलमेंट से पूर्व ख० नं० 68/8/4 रकबा 15 बिस्वा वाके ग्राम भीमपुरा स्थित आराजी के बाद सेटलमेंट बाद नवीन ख० नं० 307/1001 रकबा 0.14 है० भूमि बिरधा को नियमन की गई है ऐसी स्थिति में भूमि स्वअर्जित होना प्रमाणित हो जाता है। बिरधा के जीवनकाल में रेस्पो० द्वारा दावा प्रस्तुत किया गया जो स्वअर्जित आराजी होने से न्यायालय द्वारा वाद खारिज कर दिया गया जिसकी अपील राजस्व प्राधिकारी कोटा में जेरकार है। अतः उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपील अपीलांत स्वीकार की जावे।
- 5 विद्वान अभिभाषक रेस्पो० क्रम 1 व 3 लगायत 9 ने बहस में प्रकट किया कि न्यायालय एसीएम कोटा द्वारा दावा दिनांक 9.12.2010 को खारिज कर दिया। पिता के जीवनकाल में भूमि का बटवारा नहीं हुआ। वसीयत पर तहसीलदार ने सुनवाई की है। वसीयत में वर्णित भूमि को तहसीलदार ने पैतृक माना है। अपीलांत वसीयत के आधार पर दावा करें। नामान्तरकरण एक सरसरी कार्यवाही है जिससे किसी व्यक्ति के स्वत्व का निर्धारण नहीं किया जा सकता। अपीलांत के किसी प्रकार हक अधिकार प्रभावित हुये हैं तो नियमित वाद पेश कर उसमें साबित करें। प्रश्नगत अपील प्रकरण में अपीलांत विधिक तौर पर कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2017 (2) पेज 1355, आरआरटी 2016 (2) पेज 1099 का न्यायिक नजीर पेशकर अपील खारिज करने का अनुरोध किया।
- 6 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तथा प्रकरण में विद्वान अभिभाषक रेस्पो० क्रम 1, 3 लगायत 9 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण आरआरटी 2017 (2) पेज 1355, आरआरटी 2016 (2) पेज 1099 का आध्योपांत अवलोकन किया तथा लिखित बहस रेस्पो० क्रम-2 व बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांत एवं रेस्पो० क्रम-1, 3 ता 9 पर मनन किया। अपीलांत द्वारा दिनांक 8.8.2017 को दस्तावेज प्रकरण के निर्णय में सहायक होने से रिकार्ड पर लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजात प्रमाणित दस्तावेज होने तथा प्रकरण के निर्णय में सहायक होने से न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दस्तावेजात रिकार्ड पर लिये जाते हैं। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा स्व० बिरधा पुत्र हरलाल के नाम ग्राम भीमपुरा में दर्ज आराजी ख० नं० 232, 307, 307/1001, 680, 813, 867 कुल कित्ता 6 रकबा 3.93 है० के संदर्भ में पूर्व स्वीकृत नामान्तरकरण सं० 696 बहाल कर, बहाली का नोट दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में मृतक खातेदार बिरधा के स्थान पर समस्त सुलभी वारिसों का नाम नामान्तरकरण सं० 696 अनुसार दर्ज किये जाने का दिनांक 1.5.2017 को निर्णय पारित किया है। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलांत का मुख्य तर्क है कि

“बिरधा द्वारा उनके जीवनकाल में आराजी कुल 5 किता रकबा 2.38 है० की वसीयत दिनांक 24.4.10 को उसके पक्ष में निष्पादित की गई जो रजिस्टर्ड वसीयत है। वसीयत को सही माना किन्तु भूमि पैतृक होने से वसीयत का अधिकार नहीं होना मानकर निर्णय पारित किया गया जबकि राज० काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत खातेदार आसामी को वसीयत करने का अधिकार प्रदत्त है। भूमि पैतृक होने का पत्रावली में कोई दस्तावेज नहीं है। विवादित आराजी के संबंध में न्याया० आरएए कोटा में वाद विचाराधीन है”। अपीलान्ट के उक्त तर्क के संबंध में पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से विवादित आराजी के संबंध में अपील राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के न्यायालय में विचाराधीन होना प्रकट होता है जिसमें पक्षकारान के स्वत्व का निर्धारण होगा। प्रकरण में यह तथ्य भी विवेचनीय है कि राज० काश्तकारी अधिनियम की धारा 39 के अनुसार “खातेदार आसामी अपने भूमि-क्षेत्र में अपने हित को या हिताशं को उस व्यक्तिगत कानून के अनुसार जिसके कि वह अधीन है, अन्तिमेच्छा-पत्र के द्वारा वसीयत में दे सकता है”। चूंकि प्रश्नगत प्रकरण में खातेदार बिरधा द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त वर्णित आराजी की अपीलान्ट के पक्ष में वसीयत निष्पादित की जाना प्रकट होता है। प्रकरण में यह भी उल्लेख किया जाना भी सिमीचिन होगा कि भू राजस्व अधिनियम की धारा 135 (1) के तहत तहसीलदार को निर्विवाद मामलो में नामा० तस्दीक करने की शक्तियां प्रदान की गई है व राज० भू राजस्व अधिनियम की धारा 135 (2) में “यदि उत्तराधिकार या अन्तरण या अन्य प्रकार से अवाप्ति विवादास्पद हो तो तहसीलदार, यदि वह इस अधिनियम या तत्समय प्रभावशाली किसी अन्य विधि के अन्तर्गत सक्षम हो, विधि के अनुसार ऐसे विवाद का निर्णय करेगा और यदि इस प्रकार सक्षम न हो तो विवाद को किसी अन्य अधिकारी के पास, जो निर्णय देने में सक्षम हो, भेज देगा”। तहसीलदार लाडपुरा ने उक्त विवेचित तथ्य तथा कानूनी प्रावधानों पर गौर किये बिना जेरअपील निर्णय पारित किया है जिसे न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। लिहाजा अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार लाडपुरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 1.5.2017 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उक्त विवेचित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमांड किये जाने योग्य है।

- 7 परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्र० सं० 8, 9/2015 बउनवान राजेन्द्र कुमार बनाम रामनारायण वगेरा (रिमांड प्रकरण-द्वारा न्याया० उपखण्ड अधिकारी कोटा) में पारित निर्णय दिनांक 1.5.2017 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उक्त विवेचित तथ्यों के आलोक में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है।
- 8 निर्णय आज दिनांक 8.02.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति० सभागीय आयुक्त
कोटा